

न्यूज़ डुडे

13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ

○ इस शिखर सम्मेलन का विषय— **“ब्रिक्स@15: निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर-ब्रिक्स सहयोग”** (BRICS/15: Intra&BRICS Cooperation for Continuity] Consolidation and Consensus) था।

➤ ये उपर्युक्त चार **‘C’ (Four Cs)** एक प्रकार से ब्रिक्स साझेदारी के मूलभूत सिद्धांत हैं।

○ **प्रमुख निर्णय/संकल्प:**

- भारत के प्रधानमंत्री ने कोविड के पश्चात वैश्विक रिकवरी के लिए **‘प्रत्यास्थ, नवोन्मेषी, विश्वसनीय और संधारणीय पुनर्निर्माण’** के आदर्श वाक्य के अंतर्गत ब्रिक्स देशों के मध्य सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
- इस दौरान **‘नई दिल्ली घोषणा’** अंगीकृत की गई। इसके तहत निम्नलिखित का आह्वान किया गया:
 - ❖ शांतिपूर्ण तरीकों से अफगान संकट का समाधान करना।
 - ❖ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) सहित संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में सुधार करना।
 - ❖ ब्रिक्स ने **‘बहुपक्षीय प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा उनमें सुधार करने’** पर सामूहिक एकजुटता व्यक्त की है।
 - ❖ मानवीय संकट की स्थितियों का समाधान करना तथा महिलाओं, बच्चों एवं अल्पसंख्यकों सहित सभी के मानवाधिकारों की रक्षा करना।
- **आतंकवाद विरोधी कार्य योजना** (Action Plan on Counter-Terrorism) के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
- **अंतरिक्ष एजेंसियों तथा सुदूर संवेदी उपग्रहों पर समझौते** से वैश्विक जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, खाद्यान्न और जल संकट की रोकथाम आदि में अनुसंधान क्षमताओं में वृद्धि होगी।
- **कृषि सहयोग कार्ययोजना** (वर्ष 2021–2024) अंगीकृत की गई।

○ ब्रिक्स विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं यथा— **ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका** को एक मंच पर लाता है। यह विश्व की 41 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह है। यह समूह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 24 प्रतिशत तथा विश्व व्यापार में 16 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है।



रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (SCEP) पर भारत-अमेरिका मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया

○ **रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी** (Strategic Clean Energy Partnership: SCEP) को अप्रैल 2021 में लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान घोषित भारत-अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 के अनुरूप आरंभ किया गया है।

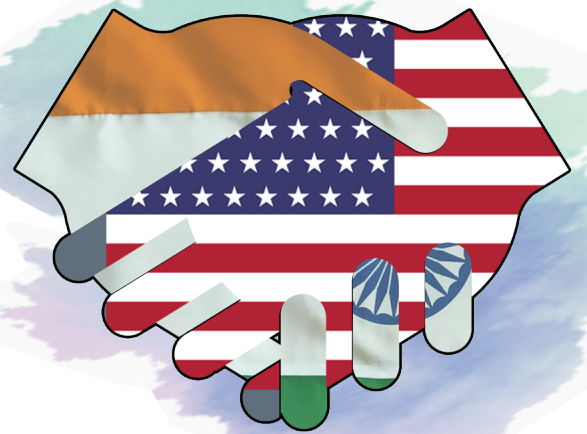
- भारत-अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के मूल में **“ऊर्जा सुरक्षा”** है।
- भारत सरकार ने भारत-अमेरिका ऊर्जा वार्ता को फरवरी 2018 में रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी का दर्जा प्रदान किया था।

○ **SCEP सहयोग के पांच स्तंभों पर अंतर-सरकारी बैठकों का आयोजन करता है।**

- विद्युत और ऊर्जा दक्षता;
- उत्तरदायी तेल एवं गैस;
- नवीनीकृत ऊर्जा;
- सतत संवृद्धि तथा
- नए उभरते ईंधन विकल्प।

○ **मुख्य बिन्दु:**

- इस दौरान उभरते ईंधनों पर एक पांचवें स्तंभ को भी शामिल करने की घोषणा की गई। यह **स्वच्छ ऊर्जा ईंधनों को प्रोत्साहन** प्रदान करने के लिए संयुक्त संकल्प की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।
- इसके अतिरिक्त, जैव ईंधन क्षेत्र में सहयोग पर विभिन्न प्रयासों की संभावना को देखते हुए जैव ईंधनों पर एक नए **भारत-अमेरिका कार्यबल (India&US Task Force on Biofuels)** की घोषणा भी की गई।
- गैस आधारित अर्थव्यवस्था के भारत के विज़न के समर्थन हेतु **गैस टास्क फोर्स** का नाम परिवर्तित कर **इंडिया-यू.एस. लो एमिशंस गैस टास्क फोर्स** करने की भी घोषणा की गई।
 - ❖ इसके तहत, **मीथेन न्यूनीकरण** पर बेहतर समझ विकसित करना भी शामिल है।
- बैठक में **भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग** पर प्रगति की भी समीक्षा की गई।
- **उन्नत स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी** (Partnership to Advance Clean Energy (PACE)—Research) के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में स्मार्ट ग्रिड तथा ग्रिड स्टोरेज को शामिल करने हेतु कार्य के दायरे का विस्तार किया जाएगा।



जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2021 का शुभारंभ किया

○ **स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2021**, ग्रामीण क्षेत्रों में ओ.डी.एफ. प्लस पहलों में तेजी लाने और ओ.डी.एफ. निरंतरता में वर्धन हेतु स्वच्छता, आरोग्यकारिता एवं साफ-सफाई का एक सर्वेक्षण है। साथ ही, यह ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) गतिविधियों में सुधार की गति बढ़ाने पर भी केंद्रित है।

➤ **पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS)** ने वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण' आरंभ किया था।

➤ **सर्वेक्षण 2021 के संचालन के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को कार्यभार सौंपा गया है।**

○ **महत्व:**

➤ यह सर्वेक्षण जमीनी स्तर पर चुनौतियों की पहचान करके और सभी राज्यों के साथ कार्य करके परिणामों में व्याप्त अंतराल को समाप्त करने में सहायता करेगा।

➤ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ने गांवों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बढ़ावा दिया है, ताकि स्वच्छ गांवों के निर्माण की दिशा में गांवों द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।

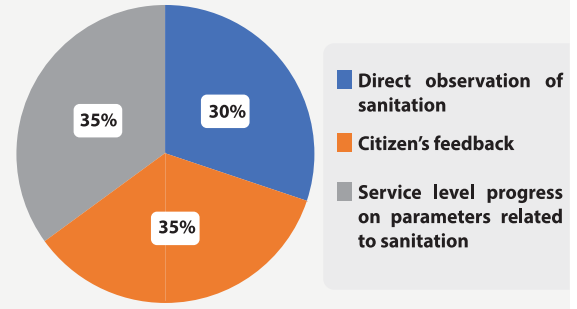
➤ **नागरिक प्रतिपुष्टि कार्यक्रम को और मजबूत करेगी।**

○ **स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2014 में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आरंभ किया गया था।**

➤ **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।**

➤ **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।**

Weightage under Swachh Surveskshan Grameen 2021



शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) के लिए 'इंडिया रैंकिंग 2021' जारी की

○ यह भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थानों (Higher Education Institutions: HEIs) को प्रदान की जाने वाली रैंकिंग का लगातार छठा संस्करण है। इसे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework: NIRF) द्वारा जारी किया गया है।

○ NIRF को शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा सितंबर 2015 में स्वीकृत किया गया था। यह ढांचा देश भर के संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है।

➤ यह देश में HEIs को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार का प्रथम प्रयास है। NIRF से पूर्व, HEIs को आमतौर पर निजी संस्थाओं द्वारा रैंकिंग प्रदान की जाती थी।

➤ वर्ष 2018 में देश भर के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए 'राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क' का हिस्सा बनना अनिवार्य कर दिया गया था।

○ सभी शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन पांच मानकों पर किया जाता है यथा— शिक्षण, अधिगम और संसाधन, अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, विस्तार व समावेशिता तथा अनुभव।

○ NIRF कुल 11 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सूचीबद्ध करता है, जो इस प्रकार हैं: समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, कॉलेज, चिकित्सा, प्रबंधन, फार्मसी, विधि, वास्तुकला, दंत चिकित्सा और अनुसंधान।

शीर्ष पाँच

रैंक	समग्र रूप से (Overall)	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (IIT Madras)	भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc)	मिरांडा हाउस, दिल्ली
2.	भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc)	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU)	श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC), दिल्ली
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई (IIT Bombay)	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU)	लोयोला कॉलेज, चेन्नई
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIT Delhi)	कलकत्ता विश्वविद्यालय	सेंट जेवियर्स महाविद्यालय, कोलकाता
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IIT Kanpur)	अमृता विश्व विद्यापीठम	रामकृष्ण मिशन विद्यामंदिर, हावड़ा

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office: NSO) के अनुसार वर्ष 2018 तक विगत पांच वर्षों में किसान परिवारों के औसत ऋणों में 57% की वृद्धि हुई थी

○ "ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों और परिवारों की भूमि जोत का स्थिति आकलन, 2019" (Situation Assessment of Agricultural Households and Land Holdings of Households in Rural India, 2019) सर्वेक्षण के नवीनतम निष्कर्ष सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी किए गए हैं।

○ **प्रमुख निष्कर्ष**

➤ वर्ष 2019 में देश में 50% से अधिक कृषक परिवार 74,121 रुपये प्रति परिवार औसत बकाया ऋण के साथ कर्ज में थे।

➤ केवल 69.6% बकाया ऋण संस्थागत स्रोतों जैसे बैंकों, सहकारी समितियों और सरकारी एजेंसियों से लिया गया था, जबकि 20.5 प्रतिशत पेशेवर साहूकारों से लिया गया था।

➤ कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान प्रति कृषक परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी।

➤ देश में कृषक परिवारों की संख्या 9.3 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की संख्या 45.8%, अनुसूचित जाति (SC) 15.9%, अनुसूचित जनजाति (ST) 14.2% और अन्य की संख्या 24.1% है।

➤ इसके अतिरिक्त, 83.5% ग्रामीण परिवारों के पास एक हेक्टेयर से भी कम भूमि है, जबकि केवल 0.2% के पास ही 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है।

○ भारत में कृषि ऋण प्रणाली: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (Priority Sector Lending: PSL); ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Scheme: ISS); किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना; स्वयं सहायता समूह – बैंक लिकेज कार्यक्रम (SHG-BPL) आदि।

तमिलनाडु में पोरुनै नदी (तामिरबरनी) सम्यता 3,200 वर्ष (1155 ईसा पूर्व) प्राचीन है

○ तमिलनाडु (TN) के तूतुकुडी जिले के शिवकलाई में एक दफन कलश में मिट्टी के साथ पाए गए चावल के अवशेष के कार्बन-14 डेटिंग विश्लेषण से उसकी अवधि (1155 ईसा पूर्व) का आकलन किया गया है।

➤ यह संभवतः वैगई सम्यता से भी प्राचीन सम्यता है। वैगई संस्कृति को 2,600 वर्ष प्राचीन माना जाता है।

○ इसकी तमिल संबद्धता की खोज में अन्य राज्यों तथा देशों में भी पुरातात्विक उत्खनन किया जाएगा।

➤ यह संभवतः वैगई सम्यता से भी प्राचीन सम्यता है। वैगई संस्कृति को 2,600 वर्ष प्राचीन माना जाता है।

➤ प्रथम चरण में मुजिरिस के प्राचीन बंदरगाह (जिसे अब केरल में पट्टनम के नाम से जाना जाता है) में उत्खनन किया जाएगा। चेर साम्राज्य की प्राचीनता व संस्कृति स्थापित करने हेतु केरल के पुरातत्वविदों के साथ संयुक्त शोध किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वेंगी, कर्नाटक के तलैकडु और ओडिशा के पलूर में भी अध्ययन किए जाएंगे।

➤ पुरातात्विक उत्खनन में शामिल किए जाने वाले देश

❖ मिस्र (कुसीर अल-कादिम और पर्निका अनेके) तथा ओमान (खोर रोरी) में तमिल लिपियों वाले मृदभांड पाए गए हैं।

❖ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश यथा- इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम आदि। इन देशों में राजा राजेंद्र चोल ने वर्चस्व स्थापित किया था।

○ वैगई सम्यता 'उद्योग और लिपि से समृद्ध एक स्वदेशी, सुविकसित आत्मनिर्भर शहरी संस्कृति थी। यह प्रतिबिंबित करती है कि उस युग के लोग अत्यधिक शिक्षित थे।

➤ निष्कर्षों ने इस सम्यता की सिंधु घाटी सम्यता के साथ तुलना को भी प्रेरित किया है, क्योंकि कई विशेषज्ञ सिंधु घाटी तथा वैगई सम्यता के बीच शहरी नियोजन में समानता की ओर संकेत करते हैं।

अन्य सुर्खियाँ

 परिवहन एवं विपणन सहायता योजना [Transport and Marketing Assistance (TMA) scheme]	○ सरकार द्वारा निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए TMA योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। इसके तहत डेयरी उत्पादों को इस योजना शामिल कर और सहायता की दरों में वृद्धि की गई है। ➤ इस योजना को कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली उच्चतर मालभाड़ा लागत हानि को कम करने के लिए आरंभ किया गया था। यह योजना मालभाड़े के अंतर्राष्ट्रीय घटक हेतु सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ➤ इस योजना के तहत सहायता की दरों में वृद्धि की गई है। समुद्री मार्ग से किए जाने वाले निर्यात के लिए 50 प्रतिशत और हवाई मार्ग से किए जाने वाले निर्यात के लिए 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
 उत्प्रवासी संरक्षी [Protectors of Emigrants (PoEs)]	○ PoEs के चौथे सम्मेलन का आयोजन 10 सितंबर को किया गया था। यह उत्प्रवास अधिनियम (Emigration Act: EA), 1983 के अधिनियमन की तिथि भी है। ○ उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत विहित प्रक्रिया के अनुसार POEs किसी आशयित उत्प्रवासियों को उत्प्रवास की निकासी (clearance) प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। ➤ इसका उद्देश्य सभी आशयित उत्प्रवासियों और उत्प्रवासियों की संरक्षा करना तथा अपनी सलाह देकर उनकी सहायता करना है। ○ उत्प्रवासी संरक्षी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन उत्प्रवासी महासंरक्षी (Protector General of Emigrants) के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन करेंगे।
 विश्व का सुदूर उत्तरी द्वीप	○ वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट के निकट अवस्थित विश्व के सुदूर उत्तरी (northernmost) द्वीप की खोज की है। ➤ यह समुद्र तल की पंक और हिमोढ़ अर्थात हिमनदों के संचलन के परिणामस्वरूप परित्यक्त मृदा, शैल और अन्य सामग्री से निर्मित एवं वनस्पति रहित द्वीप है। ➤ इससे पूर्व, ऊडाक (Oodaaq) को पृथ्वी के सुदूर उत्तरी भू-भाग के रूप में चिह्नित किया गया था। ➤ ग्रीनलैंड के हिमावरण पर वैश्विक तापन का गंभीर प्रभाव पड़ा है, परन्तु यह नया द्वीप जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। ○ ग्रीनलैंड, डेनमार्क का विशाल स्वायत्त आर्कटिक क्षेत्र है। 
 कार्बन प्रग्रहण व संचयन तकनीक [Carbon Capture and Storage (CCS) technology]	○ आइसलैंड के ओर्का में विश्व के सबसे बड़े CCS संयंत्र का परिचालन आरंभ हो गया है। यह वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का प्रग्रहण कर सकता है और इसे शैल में परिवर्तित कर सकता है। ○ CCS तकनीक के तहत जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों जैसे वृहद स्थावर स्रोतों पर CO₂ का प्रग्रहण किया जाता है। इसके उपरांत इस प्रग्रहित CO₂ का दीर्घकालिक संचयन करने के लिए उप-सतही गहराइयों में अंतःक्षेपण कर दिया जाता है। ○ इसे जलवायु परिवर्तन का सामना करने के संबंध में प्रमुख साधन के रूप में देखा जा रहा है। परन्तु, यह अत्यंत महंगा है और व्यापक स्तर पर इसके परिचालन में दशकों का समय लग सकता है।

 विश्व की प्रवाल भित्तियों की स्थिति: 2020 रिपोर्ट	○ इसे ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ वैश्विक प्रवाल भित्ति निगरानी नेटवर्क (Global Coral Reef Monitoring Network) द्वारा प्रकाशित किया गया है। ○ मुख्य निष्कर्ष: वर्ष 2010 से, लगभग सभी क्षेत्रों में औसत प्रवाल आवरण में गिरावट देखी गई है। इस प्रवाल आवरण में गिरावट मुख्य रूप से या तो समुद्री सतह के तापमान (Sea Surface Temperature: SST) में तीव्र वृद्धि संबंधी असंगति या निरंतर उच्च SST संबंधी असंगति के कारण हुई है। ➤ प्रवाल एक अकशेरुकी जीव होता है। यह रंगीन जीवों के एक वृहद समूह नाइडेरिया (Cnidaria) से संबंधित है। ➤ प्रवाल विरंजन: जब ताप या प्रदूषण जैसी दशाओं के कारण प्रवाल प्रभावित होती हैं, तो उनसे शैवाल (जूजैन्थेली) पृथक हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रवाल रंगहीन (सफेद) कंकाल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।
 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर अवशेष प्राप्त हुए	○ इस संरचनात्मक मंदिर की खोज एटा (उत्तर प्रदेश) के बिलसड में हुई है, जो एक ज्ञात गुप्त कालीन बस्ती है। ○ यह अब तक खोजा गया गुप्त काल का तीसरा (अन्य दो देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर देहात का भीतरगांव मंदिर हैं) संरचनात्मक मंदिर है। ○ इसका निर्माण ब्राह्मणों, जैनियों और बौद्धों के लिए किया गया था। ○ इस मंदिर की सीढ़ियों पर शंखलिपी शैली और कुमारगुप्त प्रथम (5वीं शताब्दी के दौरान उत्तर-मध्य भारत का गुप्त शासक) को प्रदान की गई 'श्री महेंद्रदित्य' की उपाधि उत्कीर्णित हैं। ○ सर्वप्रथम गुप्त शासकों ने संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया था। यह प्राचीन शैल कर्तित उपासना स्थलों में एक विशिष्ट परिवर्तन था।
 सुखियों में रहे व्यक्तित्व	आचार्य विनोबा भावे (11 सितंबर 1895 – 15 नवंबर 1982) ○ उन्हें एक महान विद्वान-संत के रूप में स्मरण किया जाता है। वे 20वीं शताब्दी के गांधीवादी विचारक थे। उन्होंने अहिंसा और मानवाधिकारों का समर्थन किया था। ○ वह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनारस महाविद्यालय में महात्मा गांधी के भाषण से प्रेरित हुए थे। ○ उन्हें भूदान आंदोलन या 'रक्तहीन क्रांति' के लिए जाना जाता है, जो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से आरंभ हुआ एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ○ प्रकाशन: गीता प्रवचन; तीसरी शक्ति; स्वराज्य शास्त्र; भूदान गंगा; मूड बाय लव आदि। ○ विनोबा भावे वर्ष 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे। उन्हें वर्ष 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

